रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 मार्च, 1984/6 चैत्र, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

शिमला-4, 21 मार्च, 1984

संख्या 1-19/84-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग

539-राजपत्र/84—26-3-84—1,145.

मूल्य : 20 पैसे ।

विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 7) जो दिनांक 21 मार्च, 1984 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

2% in the

विश्वेश्वर

सचिव ।

1984 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धन राशि के भुगतान की स्वीकृति और उनके विनियोग हेतु —

विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1984 कहलायेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1983-84 वर्ष के लिए 45,24,78,339 रुपये की और राशि निकालना।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां जिनका जोड़ पैंतालीस करोड़, चौबीस लाख, अठत्तर हज़ार, तीन सौ उनतालीस रुपये आता है निकाली जाए और उनका वित्तीय वर्ष 1983-84 की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

विनियोग।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को निकालने और उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धन राशियों का विनियोग, धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जायेगा।

अनुसूची

(देखिए धारा 2 तथा 3)

1	2		3	4% in the	
			निम्नलिखित राशियों से अनाधिक		
मांग संख्या	सेवायें एवं प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा तथा निर्वाचन	(राजस्व)	—	27,000	27,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्रि परिषद्	(राजस्व)	—	2,89,500	2,89,500
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	5,90,000	—	5,90,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	53,20,000	—	53,20,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	34,77,000	—	34,77,000
6	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	10,10,000	25,409	10,35,409
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	(राजस्व)	1,15,48,000	—	1,15,48,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	(राजस्व)	4,16,87,000	—	4,16,87,000
		(पूंजी)	42,83,000	—	42,83,000
9	चिकित्सा और परिवार नियोजन	(पूंजी)	40,70,000	—	40,70,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	7,15,01,000	—	7,15,01,000
		(पूंजी)	12,34,500	—	12,34,500
11	कृषि	(राजस्व)	4,16,60,000	41,676	4,17,01,676
		(पूंजी)	1,55,00,000	—	1,55,00,000
12	लघु सिंचाई	(राजस्व)	51,97,000	—	51,97,000
		(पूंजी)	5,00,000	—	5,00,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(राजस्व)	51,02,000	—	51,02,000
14	पशु पालन तथा दुग्ध विकास	(राजस्व)	3,23,000	49,600	3,72,600
		(पूंजी)	1,00,000	—	1,00,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	2,05,000	—	2,05,000
16	वन	(राजस्व)	2,000	16,68,100	16,70,100
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	2,87,90,000	—	2,87,90,000
		(पूंजी)	70,02,000	8,97,395	78,99,395
18	सप्लाई, उद्योग तथा खनिज	(राजस्व)	2,99,000	—	2,99,000
		(पूंजी)	1,05,00,000	—	1,05,00,000
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेलें	(राजस्व)	7,06,000	—	7,06,000
		(पूंजी)	2,15,000	—	2,15,000
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	(राजस्व)	50,53,000	—	50,53,000
		(पूंजी)	34,50,000	—	34,50,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
	सामुदायिक विकास	(राजस्व)	2,08,48,000	—	2,08,48,000
	महकारिता	(राजस्व)	19,12,600	314	19,12,914
	[illegible]वं पोषाहार	(राजस्व)	1,000	—	1,000
		(पूंजी)	24,00,000	645	24,00,645
24	जल तथा विद्युत विकास	(राजस्व)	1,05,44,000	—	1,05,44,000
		(पूंजी)	6,60,00,000	—	6,60,00,000
25	सिंचाई, नाव चालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	5,50,000	—	5,50,000
		(पूंजी)	4,22,000	—	4,22,000
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(पूंजी)	13,68,000	—	13,68,000
27	सड़क परिवहन	(राजस्व)	30,000	—	30,000
28	पर्यटन	(राजस्व)	11,000	—	11,000
		(पूंजी)	40,000	—	40,000
29	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	3,53,000	—	3,53,000
		(पूंजी)	2,13,400	1,47,600	3,61,000
30	आवास	(राजस्व)	—	7,100	7,100
		(पूंजी)	27,20,000	6,500	27,26,500
31	नगर विकास	(राजस्व)	40,00,000	—	40,00,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	(राजस्व)	1,01,38,000	—	1,01,38,000
33	वित्त	(राजस्व)	2,79,79,000	1,46,63,000	4,26,42,000
		(पूंजी)	—	46,15,000	46,15,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	25,00,000	—	25,00,000
35	जनजातीय विकास	(राजस्व)	64,85,000	—	64,85,000
		(पूंजी)	22,00,000	—	22,00,000
	कुल जोड़	..	43,00,39,500	2,24,38,839	45,24,78,339

उद्देश्य तथा कारणों का कथन

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल ... राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20... (1) के अनुसार पुरःस्थापित प्रस्तुत किया जाता है।

...% in the

...णियों से अनाधिक

शिमला :
21 मार्च, 1984

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन-ए-सी-(2) 14/83 भाग II]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने तथा उस पर सभा द्वारा विचार किये जाने का अभिस्ताव किया है।

[*Authorised English Text of the Himachal Pradesh Viniyog Vidhaik, 1984, as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

Bill No. 7 of 1984

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1984

जल तथा ~ (AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the Services for the year ending on the 31*st day of March*, 1984.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1984.

Issue of a further sum of Rs. 45,24,78,339 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the year, 1983-84.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of forty-five crores, twenty-four lakhs, seventy-eight thousand, three hundred and thirty-nine rupees towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year, 1983-84 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
No. of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections	(Revenue) ...	—	27,000	27,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue) ...	—	2,89,500	2,89,500
3	Administration of Justice	(Revenue) ...	5,90,000	—	5,90,000
4	General Administration	(Revenue) ...	53,20,000	—	53,20,000
5	Land Revenue	(Revenue) ...	34,77,000	—	34,77,000
6	Excise and Taxation	(Revenue) ...	10,10,000	25,409	10,35,409
7	Police and Fire Protection	(Revenue) ...	1,15,48,000	—	1,15,48,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	(Revenue)	4,16,87,000	—	4,16,87,000
		(Capital) ...	42,83,000	—	42,83,000
9	Medical and Family Planning	(Capital) ...	40,70,000	—	40,70,000
10	Public Works	(Revenue) ...	7,15,01,000	—	7,15,01,000
		(Capital) ...	12,34,500	—	12,34,500
11	Agriculture	(Revenue) ...	4,16,60,000	41,676	4,17,01,676
		(Capital) ...	1,55,00,000	—	1,55,00,000
12	Minor Irrigation	(Revenue) ...	51,97,000	—	51,97,000
		(Capital) ...	5,00,000	—	5,00,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue) ...	51,02,000	—	51,02,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue) ...	3,23,000	49,600	3,72,600
		(Capital) ...	1,00,000	—	1,00,000
15	Fisheries	(Revenue) ...	2,05,000	—	2,05,000
16	Forests	(Revenue) ...	2,000	16,68,100	16,70,100
17	Roads and Bridges	(Revenue) ...	2,87,90,000	—	2,87,90,000
		(Capital) ...	70,02,000	8,97,395	78,99,395
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue) ...	2,99,000	—	2,99,000
		(Capital) ...	1,05,00,000	—	1,05,00,000
19	Social Security, Welfare and Jails	(Revenue) ...	7,06,000	—	7,06,000
		(Capital) ...	2,15,000	—	2,15,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply	(Revenue) ...	50,53,000	—	50,53,000
		(Capital) ...	34,50,000	—	34,50,000
21	Community Development	(Revenue) ...	2,08,48,000	—	2,08,48,000
22	Co-operation	(Revenue) ...	19,12,600	314	19,12,914
23	Food and Nutrition	(Revenue) ...	1,000	—	1,000
		(Capital) ...	24,00,000	645	24,00,645
24	Water and Power Development	(Revenue) ...	1,05,44,000	—	1,05,44,000
		(Capital) ...	6,60,00,000	—	6,60,00,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control	(Revenue) ...	5,50,000	—	5,50,000
		(Capital) ...	4,22,000	—	4,22,000
26	Stationery and Printing	(Capital) ...	13,68,000	—	13,68,000
27	Road Transport	(Revenue) ...	30,000	—	30,000
28	Tourism	(Revenue) ...	11,000	—	11,000
		(Capital) ...	40,000	—	40,000
29	Labour and Employment	(Revenue) ...	3,53,000	—	3,53,000
		(Capital) ...	2,13,400	1,47,600	3,61,000
30	Housing	(Revenue) ...	—	7,100	7,100
		(Capital) ...	27,20,000	6,500	27,26,500
31	Urban Development	(Revenue) ...	40,00,000	—	40,00,000
32	Other Administrative Services	(Revenue) ...	1,01,38,000	—	1,01,38,000
33	Finance	(Revenue) ...	2,79,79,000	1,46,63,000	4,26,42,000
		(Capital) ...	—	46,15,000	46,15,000
34	Loans to Government Servants	(Capital) ...	25,00,000	—	25,00,000
35	Tribal Development	(Revenue) ...	64,85,000	—	64,85,000
		(Capital)	22,00,000	—	22,00,000
	Grand Total	...	43,00,39,500	2,24,38,839	45,24,78,339

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year, 1983-84.

SHIMLA:
The 21st March, 1984.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(2)14/83 Pt. II]

The Governor, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1984, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction, and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

शिमला-4, 21 मार्च, 1984

संख्या 1-21/84-वि0स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 8) जो दिनांक 21 मार्च, 1984 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव ।

1984 का विधेयक संख्यांक 8.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 1984-85 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियां चुकाने और उनका विनियोग करने हेतु

विधेयक ।

यह भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1984 कहलाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वर्ष 1984-85 के लिए 48,52,90,000 रुपए की राशि निकालना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां, जिनका जोड़ अड़तालीस करोड़, बावन लाख, नब्बे हज़ार रुपये है निकाली जाए और वित्तीय वर्ष 1984-85 के पहले एक माम की अवधि म अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु, उपयोग किया जाए ।

विनियोग

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन धन राशियों को निकालने और उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धनराशियों का विनियोग, धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जायेगा ।

अनुसूची

(देखिये धारायें 2 और 3)

1	2		3		
अनुदान क्रमांक	सेवाएं तथा प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनाधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा तथा निर्वाचन	(राजस्व)	14,22,000	14,000	14,36,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	3,12,000	1,26,000	4,38,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	11,95,000	3,62,000	15,57,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	62,41,000	1,25,000	63,66,000
		(पूंजी)	4,000	—	4,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	47,49,000	—	47,49,000
		(पूंजी)	72,000	—	72,000
6	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	14,47,000	—	14,47,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	(राजस्व)	1,09,59,000	—	1,09,59,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	(राजस्व)	5,00,53,000	—	5,00,53,000
		(पूंजी)	9,91,000	—	9,91,000
9	चिकित्सा और परिवार नियोजन	(राजस्व)	1,68,00,000	—	1,68,00,000
		(पूंजी)	23,15,000	—	23,15,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	2,92,30,000	—	2,92,30,000
		(पूंजी)	16,67,000	—	16,67,000
11	कृषि	(राजस्व)	1,62,85,000	—	1,62,85,000
		(पूंजी)	67,99,000	—	67,99,000
12	लघु सिंचाई	(राजस्व)	86,77,000	—	86,77,000
		(पूंजी)	19,26,000	—	19,26,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(राजस्व)	52,77,000	—	52,77,000
		(पूंजी)	4,00,000	—	4,00,000
14	पशुपालन तथा दुग्ध विकास	(राजस्व)	47,18,000	—	47,18,000
		(पूंजी)	5,88,000	—	5,88,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	4,39,000	—	4,39,000
		(पूंजी)	1,33,000	—	1,33,000
16	वन	(राजस्व)	1,32,94,000	—	1,32,94,000
		(पूंजी)	14,16,000	—	14,16,000
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	80,50,000	—	80,50,000
		(पूंजी)	2,24,00,000	—	2,24,00,000
18	सफाई, उद्योग तथा खनन	(राजस्व)	79,36,000	—	79,36,000
		(पूंजी)	19,41,000	—	19,41,000

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेलें	(राजस्व)	63,93,000	—	63,93,000
		(पूंजी)	6,01,000	—	6,01,000
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	(राजस्व)	2,82,44,000	—	2,82,44,000
		(पूंजी)	80,50,000	—	80,50,000
21	सामुदायिक विकास	(राजस्व)	1,15,74,000	—	1,15,74,000
		(पूंजी)	15,000	—	15,000
22	सहकारिता	(राजस्व)	24,78,000	—	24,78,000
		(पूंजी)	14,54,000	—	14,54,000
23	खाद्य एवं पोषाहार	(राजस्व)	29,92,000	—	29,92,000
		(पूंजी)	72,14,000	—	72,14,000
24	जल तथा विद्युत विकास	(राजस्व)	12,25,000	—	12,25,000
		(पूंजी)	2,44,71,000	—	2,44,71,000
25	सिंचाई, नाव चालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	9,27,000	—	9,27,000
		(पूंजी)	14,81,000	—	14,81,000
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(राजस्व)	13,53,000	—	13,53,000
		(पूंजी)	2,50,000	—	2,50,000
27	सड़क परिवहन	(राजस्व)	1,47,000	—	1,47,000
		(पूंजी)	18,74,000	—	18,74,000
28	पर्यटन	(राजस्व)	4,28,000	—	4,28,000
		(पूंजी)	10,35,000	—	10,35,000
29	श्रम तथा रोज़गार	(राजस्व)	12,98,000	—	12,98,000
		(पूंजी)	1,13,000	—	1,13,000
30	आवास	(राजस्व)	5,32,000	—	5,32,000
		(पूंजी)	15,57,000	—	15,57,000
31	नगर विकास	(राजस्व)	30,88,000	—	30,88,000
		(पूंजी)	5,41,000	—	5,41,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवायें	(राजस्व)	88,33,000	—	88,33,000
		(पूंजी)	1,63,000	—	1,63,000
33	वित्त	(राजस्व)	81,45,000	2,19,62,000	3,01,07,000
		(पूंजी)	—	8,06,25,000	8,06,25,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	19,00,000	—	19,00,000
35	जनजातीय विकास	(राजस्व)	1,79,88,000	—	1,79,88,000
		(पूंजी)	79,67,000	—	79,67,000
	कुल जोड़	..	38,20,76,000	10,32,14,000	48,52,90,000

उद्देश्य तथा कारणों का कथन

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1984-85 के पहले एक मास के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय, पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 व 204 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा न होने तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 की धारा (1) व अनुच्छेद 206 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है । मांगी गई राशि में वर्ष 1984-85 में रखी गई नई स्कीमों के प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
मार्च 21, 1984.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिन-ए-सी (1) 26/83]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने तथा उस पर सभा द्वारा विचार किए जाने का अभिस्ताव किया है ।

[*Authorised English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Lekhanudan) Vidheyak*, 1984 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 8 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1984

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year, 1984-85.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1984. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of forty-eight crores, fifty-two lakhs and ninety thousand rupees towards defraying several charges which will come in course of payment during the first one month of the financial year, 1984-85 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule. Withdrawal of Rs. 48,52,90,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1984-85.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections	(Revenue)	14,22,000	14,000	14,36,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	3,12,000	1,26,000	4,38,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	11,95,000	3,62,000	15,57,000
4	General Administration	(Revenue)	62,41,000	1,25,000	63,66,000
		(Capital)	4,000	—	4,000
5	Land Revenue	(Revenue)	47,49,000	—	47,49,000
		(Capital)	72,000	—	72,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	14,47,000	—	14,47,000
7	Police and Fire Protection	(Revenue)	1,09,59,000	—	1,09,59,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	(Revenue)	5,00,53,000	—	5,00,53,000
		(Capital)	9,91,000	—	9,91,000
9	Medical and Family Planning	(Revenue)	1,68,09,000	—	1,68,09,000
		(Capital)	23,15,000	—	23,15,000
10	Public Works	(Revenue)	2,92,30,000	—	2,92,30,000
		(Capital)	16,67,000	—	16,67,000
11	Agriculture	(Revenue)	1,62,85,000	—	1,62,85,000
		(Capital)	67,99,000	—	67,99,000
12	Minor Irrigation	(Revenue)	86,77,000	—	86,77,000
		(Capital)	19,26,000	—	19,26,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	52,77,000	—	52,77,000
		(Capital)	4,00,000	—	4,00,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	47,18,000	—	47,18,000
		(Capital)	5,88,000	—	5,88,000
15	Fisheries	(Revenue)	4,39,000	—	4,39,000
		(Capital)	1,33,000	—	1,33,000
16	Forest	(Revenue)	1,32,94,000	—	1,32,94,000
		(Capital)	14,16,000	—	14,16,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	80,50,000	—	80,50,000
		(Capital)	2,24,00,000	—	2,24,00,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	79,36,000	—	79,36,000
		(Capital)	19,41,000	—	19,41,000
19	Social Security, Welfare and Jails	(Revenue)	63,93,000	—	63,93,000
		(Capital)	6,01,000	—	6,01,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply	(Revenue)	2,82,44,000	—	2,82,44,000
		(Capital)	80,50,000	—	80,50,000
21	Community Development	(Revenue)	1,15,74,000	—	1,15,74,000
		(Capital)	15,000	—	15,000
22	Co-operation	(Revenue)	24,78,000	—	24,78,000
		(Capital)	14,54,000	—	14,54,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Food and Nutrition	(Revenue)	29,92,000	—	29,92,000
		(Capital)	72,14,000	—	72,14,000
24	Water and Power Development	(Revenue)	12,25,000	—	12,25,000
		(Capital)	2,44,71,000	—	2,44,71,000
25	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control	(Revenue)	9,27,000	—	9,27,000
		(Capital)	14,81,000	—	14,81,000
26	Stationery and Printing	(Revenue)	13,53,000	—	13,53,000
		(Capital)	2,50,000	—	2,50,000
27	Road Transport	(Revenue)	1,47,000	—	1,47,000
		(Capital)	18,74,000	—	18,74,000
28	Tourism	(Revenue)	4,28,000	—	4,28,000
		(Capital)	10,35,000	—	10,35,000
29	Labour and Employment	(Revenue)	12,98,000	—	12,98,000
		(Capital)	1,13,000	—	1,13,000
30	Housing	(Revenue)	5,32,000	—	5,32,000
		(Capital)	15,57,000	—	15,57,000
31	Urban Development	(Revenue)	30,88,000	—	30,88,000
		(Capital)	5,41,000	—	5,41,000
32	Other Administrative Services	(Revenue)	88,33,000	—	88,33,000
		(Capital)	1,63,000	—	1,63,000
33	Finance	(Revenue)	81,45,000	2,19,62,000	3,01,07,000
		(Capital)	—	8,06,25,000	8,06,25,000
34	Loans to Government Servants	(Capital)	19,00,000	—	19,00,000
35	Tribal Development	(Revenue)	1,79,88,000	—	1,79,88,000
		(Capital)	79,67,000	—	79,67,000
	Grand Total	...	38,20,76,000	10,32,14,000	48,52,90,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly equal to 1/12th of the estimated expenditure of Government of Himachal Pradesh for the financial year 1984-85 pending the completion of the procedure prescribed in Articles 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes included in the Budget for the year 1984-85.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 21st March, 1984.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C (1) 26/83]

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1984 recommends under Article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।